



सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बदला घुसपैठ का खेल, जम्मू के इलाकों पर बढ़ा आतंकी दबाव

नई दिल्ली। वर्ष 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद नियंत्रण रेखा के पार से आतंकियों की घुसपैठ की रणनीति में बदलाव के संकेत मिले हैं। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, पहले कश्मीर घाटी के आसपास मौजूद रहे कई पारंपरिक लॉन्चपैडों के बजाय घुसपैठ की कोशिशों का ध्यान जम्मू संभाग के पुंछ, राजौरी और कठुआ से लगे इलाकों की ओर बढ़ा है। इन क्षेत्रों का भौगोलिक स्वरूप, नदी-नालों की मौजूदगी और ऊबड़-खाबड़ जमीन सुरक्षा बलों के लिए अलग तरह की चुनौती पैदा करती है। हाल के वर्षों में सुरक्षा तंत्र ने भी इसी बदलते पैटर्न को ध्यान में रखते हुए निगरानी और घुसपैठ रोधी व्यवस्था में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया है।

अधिकारियों के मुताबिक, 2016 की कार्रवाई ने सीमा पार आतंकी ढांचे के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया को लेकर एक नया संकेत दिया। इसके बाद नियंत्रण रेखा के आसपास आतंकियों की आवाजाही रोकने के लिए सैन्य और खुफिया तंत्र ने अपने निगरानी ढांचे को लगातार मजबूत किया। भारतीय सेना पहले से ही घुसपैठ रोकने के लिए मानव संसाधन के साथ निगरानी उपकरण, रडार, नाइट विजन, हवाई निगरानी और

जमीन के भीतर गतिविधियों का पता लगाने वाले सेंसरों का इस्तेमाल करती रही है। रक्षा मंत्रालय ने 2021 में भी संसद में बताया था कि सीमा पर एंटी-इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम को आधुनिक तकनीक से लगातार उन्नत किया जा रहा है और इसमें स्मार्ट उपकरण, लेजर फेंस तथा बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम जैसे साधन शामिल किए जा रहे हैं। ताजा सुरक्षा आकलनों के अनुसार, घुसपैठ के संभावित रास्तों में बदलाव के साथ जम्मू के पुंछ, राजौरी और कठुआ सेक्टरों पर विशेष ध्यान दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि कश्मीर के कुछ पारंपरिक रास्तों पर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के बाद सीमा पार से घुसपैठ कराने वाले नेटवर्कों ने कठिन भौगोलिक इलाकों को वैकल्पिक रास्ते के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की। पुंछ और राजौरी का पहाड़ी तथा जंगल वाला इलाका और कठुआ-सांबा क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए अलग प्रकार की चुनौती पेश करती हैं। वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत सरकार की ओर से जारी जानकारी में जम्मू-कश्मीर के पुंछ-राजौरी क्षेत्र और जम्मू के अन्य संवेदनशील इलाकों में आतंकी ढांचे तथा घुसपैठ की कोशिशों को लेकर सुरक्षा चिंताओं का उल्लेख किया



गया था। नियंत्रण रेखा की सुरक्षा व्यवस्था में तकनीक की भूमिका भी लगातार बढ़ी है। उपलब्ध अधिकारियों के आकलन के अनुसार करीब 740 किलोमीटर लंबी एलओसी पर लगी बाड़ के बड़े हिस्से को स्मार्ट निगरानी प्रणाली से जोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। हालिया रिपोर्टों में करीब 700 किलोमीटर हिस्से के स्मार्ट फेंस सिस्टम से जुड़े होने का दावा किया गया है। इस व्यवस्था में ऑप्टिकल, थर्मल, ध्वनिक और इन्फ्रारेड सेंसर तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कैमरों का इस्तेमाल किए जाने

की बात कही गई है। इसका उद्देश्य संदिग्ध गतिविधियों का शुरुआती स्तर पर पता लगाना और निगरानी केंद्रों तक वास्तविक समय में जानकारी पहुंचाना है। सीमा सुरक्षा में इस तकनीकी बदलाव का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि घुसपैठ की कोशिशों केवल रात के अंधेरे या पारंपरिक रास्तों तक सीमित नहीं रहतीं। पहाड़ी क्षेत्रों, जंगलों, नालों और नदी के आसपास की जमीन में प्राकृतिक आड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में केवल जवानों की प्रत्यक्ष निगरानी पर निर्भर रहने के बजाय सेंसर,

कैमरा, रडार और अन्य निगरानी साधनों को एक साथ इस्तेमाल करने की रणनीति अपनाई जा रही है। रक्षा मंत्रालय पहले ही बता चुका है कि घुसपैठ रोधी तंत्र में हवाई प्लेटफॉर्म, नाइट विजन उपकरण, रडार और अंडरग्राउंड सेंसर सहित कई तकनीकों को शामिल किया गया है। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशों में सुरंगों का इस्तेमाल भी एक चुनौती के रूप में सामने आया है। जम्मू क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े इलाकों में अतीत में भूमिगत सुरंगों का पता लगाया गया है और सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसी गतिविधियों का पता लगाने के लिए जमीन के भीतर होने वाले बदलावों और कंपन की निगरानी करने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया है। हालिया अधिकारियों के आकलन में भूमिगत गतिविधियों का पता लगाने के लिए भूकंपीय सेंसर और जमीन की संरचना में बदलाव पकड़ने वाली तकनीक के इस्तेमाल का भी उल्लेख किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निगरानी व्यवस्था केवल सतह तक सीमित न रहे। घुसपैठ की रणनीति में एक और बदलाव आतंकियों की संख्या और प्रशिक्षण के स्तर से जुड़ा बताया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार पहले बड़ी संख्या में कम प्रशिक्षित आतंकियों

को सीमा पार भेजने की कोशिश की जाती थी, जबकि अब छोटे समूहों में अधिक प्रशिक्षित आतंकियों को भेजने की कोशिशों पर जोर दिखाई देता है। हाल के वर्षों में दो-दो आतंकियों के समूहों में घुसपैठ के प्रयासों की बात भी सुरक्षा अधिकारियों ने कही है। इस बदलाव का उद्देश्य बड़ी संख्या में लोगों को भेजने के बजाय सीमित संख्या में प्रशिक्षित लोगों के जरिए लंबे समय तक गतिविधियां संचालित करना बताया जाता है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि छोटे समूहों की पहचान और उन्हें ट्रैक करना बड़ी संख्या में घुसपैठियों की तुलना में अलग चुनौती पेश करता है। यदि कुछ प्रशिक्षित आतंकी सीमा पार करने में सफल होते हैं, तो उनके लिए स्थानीय संघर्षों, ओवरग्राउंड नेटवर्क या अन्य सहायता तंत्र का इस्तेमाल करने की संभावना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बनती है। इसी कारण जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ रोधी अभियान के साथ-साथ अंदरूनी इलाकों में खुफिया नेटवर्क और निगरानी को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय के हालिया दस्तावेज में भी नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों तथा ड्रोन के जरिए हथियार और

मादक पदार्थ पहुंचाने के प्रयासों का उल्लेख किया गया है। घुसपैठ के रास्तों में बदलाव को समझने के लिए 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक का संदर्भ भी महत्वपूर्ण है। उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकी लॉन्चपैडों को निशाना बनाया था। उस समय भी सैन्य कार्रवाई के लिए ऐसे स्थानों की पहचान की गई थी जिन्हें घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों से जोड़ा गया था। बाद के वर्षों में बालाकोट हवाई कार्रवाई और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत ने सीमा पार आतंकी ढांचे को निशाना बनाने की नीति प्रदर्शित की। रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर के संबंध कश्मीर में आतंकवादी ढांचे से जुड़े नौ स्थानों को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान की ओर से घुसपैठ और सीमा पार आतंकी ढांचे को लेकर सतर्कता जारी रखने की बात कही गई है। रक्षा मंत्रालय के 2025-26 के आधिकारिक दस्तावेज में कहा गया कि पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा के संभावित आतंकियों को गुप्त रूप से घुसाने के प्रयास बढ़े हैं। इसमें पुंछ-राजौरी क्षेत्र को

प्रॉक्सी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने के प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही जम्मू क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से हथियार और मादक पदार्थ पहुंचाने तथा आतंकियों की घुसपैठ के प्रयासों का उल्लेख किया गया है। इस बदलते परिदृश्य में सीमा सुरक्षा अब केवल बाड़ और चौकियों तक सीमित नहीं रह गई है। आधुनिक निगरानी व्यवस्था में सेंसर, कैमरे, रडार, ड्रोन, संचार नेटवर्क और खुफिया सूचनाओं को एक साथ इस्तेमाल करने पर जोर बढ़ा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कैमरों और सेंसरों से मिलने वाली सूचनाओं को नियंत्रण केंद्रों तक पहुंचाकर संदिग्ध गतिविधियों का विश्लेषण करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वायत्त प्रणालियों, डेटा विश्लेषण और सुरक्षित संचार नेटवर्क जैसे क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। हालांकि घुसपैठ के तरीकों में बदलाव का आकलन लगातार बदलती परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सीमा पार आतंकी संगठनों की गतिविधियां, मौसम, भौगोलिक परिस्थितियां, सुरक्षा बलों की तैनाती, स्थानीय नेटवर्क और तकनीकी निगरानी सभी कारक इसमें भूमिका निभाते हैं।

कूरियर नेटवर्क की आड़ में 475 करोड़ का सोना देशभर में पहुंचाया, मास्टरमाइंड समेत 11 गिरफ्तार

नई दिल्ली। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने देश के कई बड़े शहरों में फैले एक संगठित सोना तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए विदेशी मूल के तस्करी किए गए सोने की बड़ी खेप बरामद की है। डीआरआई की ओर से 23 और 24 सितंबर को मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद और गुवाहाटी में एक साथ की गई कार्रवाई के दौरान करीब 10.36 करोड़ रुपये मूल्य का 6.61 किलोग्राम विदेशी सोना जन्म किया गया। इस मामले में गिरोह के कथित मास्टरमाइंड समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि तस्करी का यह नेटवर्क केवल एक शहर तक सीमित नहीं था, बल्कि सीमा से लेकर देश के अलग-अलग महानगरों तक फैले कूरियर तंत्र के जरिए सोने की आपूर्ति की जा रही थी। जांच एजेंसी को सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल और अरुण से लगी भारत-बांग्लादेश सीमा के रास्ते विदेशी सोने की खेप देश में पहुंचाई जा रही है। इसके बाद इस सोने को सीधे बड़े खरीदारों या तस्करी नेटवर्क से जुड़े लोगों तक भेजने के बजाय कूरियर के माध्यम से अलग-अलग शहरों में छोटी-छोटी खेपों में पहुंचाया जाता था। इस सूचना के आधार पर डीआरआई ने नेटवर्क से जुड़े ठिकानों और संदिग्ध कूरियर कंसाइनमेंट पर निगरानी



बढ़ाई। कार्रवाई के दौरान गुवाहाटी और कोलकाता से मुंबई, दिल्ली तथा अहमदाबाद भेजी जा रही सोने की खेपों का पता लगाया गया और उन्हें जल कर लिया गया। डीआरआई के अधिकारियों के मुताबिक, तस्करी के सोने को एक साथ बड़ी खेप के रूप में भेजने के बजाय गिरोह उसे कई छोटे कूरियर कंसाइनमेंट में बांट देता था। इसके बाद अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पर इन खेपों को देश के विभिन्न शहरों में भेजा जाता था। इस तरीके का इस्तेमाल कथित तौर पर तस्करी की पूरी खेप को एक साथ पकड़े जाने से बचाने और नेटवर्क में शामिल अलग-अलग स्तर के लोगों के बीच दूरी बनाए रखने के लिए किया जाता था। प्रत्येक कंसाइनमेंट को अलग व्यक्ति के माध्यम से भेजे जाने के कारण पूरे नेटवर्क की कड़ियों तक पहुंचना जांच एजेंसी के लिए चुनौतीपूर्ण था।

कार्रवाई के दौरान कूरियर के जरिए भेजे गए कंसाइनमेंट हासिल करने वाले सात लोगों को पकड़ा गया। इसके बाद डीआरआई ने कोलकाता में उन स्थानों पर भी तलाशी अभियान चलाया, जहां से सोने की खेपों को भेजने की व्यवस्था की जा रही थी। कंसाइनर और शिपर से जुड़े ठिकानों की तलाशी के दौरान तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच आगे बढ़ने पर मुंबई में सोने की खेप पहुंचाने और उसकी डिलीवरी कराने वाले व्यक्ति की भूमिका सामने आई। एजेंसी ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। डीआरआई के अनुसार, यही व्यक्ति नेटवर्क के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था और उसे इस मामले का कथित मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जांच में इस नेटवर्क के काम करने के तरीके से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। एजेंसी के अनुसार, कंसाइनर, शिपर और कूरियर से सोना प्राप्त करने वाले लोगों की भूमिका अलग-अलग स्तर पर तय थी। कामगiri तौर पर इन लोगों के नाम कंसाइनमेंट से जुड़े थे, लेकिन उनके पास सोने की खरीद-बिक्री अथवा वैध कारोबार से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। जांचकर्ताओं को संदेह है कि इन व्यक्तियों का इस्तेमाल तस्करी के सोने को एक स्थान से दूसरे स्थान तक

पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। जन्म किया गया विदेशी सोना सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के तहत कब्जे में लिया गया है। बरामद सोने की कुल मात्रा 6.61 किलोग्राम बताई गई है, जिसकी कीमत करीब 10.36 करोड़ रुपये आंकी गई है। हालांकि जांच एजेंसी के लिए इस बरामदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण वह पूरा नेटवर्क है, जिसके जरिए लंबे समय से सोने की खेप देश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाए जाने का आरोप है। दस्तावेजों और उपलब्ध सूचनाओं की पड़ताल में इस नेटवर्क की गतिविधियों का दायरा काफी बड़ा होने के संकेत मिले हैं। डीआरआई के मुताबिक, दस्तावेजों की जांच के दौरान पता चला कि इसी कूरियर नेटवर्क के माध्यम से चालू वर्ष के पहले नौ महीनों में करीब 318 किलोग्राम तस्करी का सोना देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जा चुका है। इस सोने का अनुमानित मूल्य लगभग 475 करोड़ रुपये बताया गया है। यानी सितंबर तक जिस नेटवर्क की एक खेप डीआरआई के हाथ लगी, उसके पीछे कई महीनों से चल रही कथित तस्करी की एक बड़ी श्रृंखला का पता चला है। एजेंसी अब उन सभी कंसाइनमेंट, कूरियर बुकिंग, भुगतान और डिलीवरी से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है, जिनके जरिए यह सोना अलग-अलग शहरों तक पहुंचाया गया।

देश के ताप बिजली संयंत्रों में घट रहा कोयले का भंडार 80 संयंत्रों में जरूरत के 25 फीसदी से भी कम स्टॉक

नई दिल्ली। देश में बिजली की बढ़ती मांग के बीच ताप बिजली संयंत्रों में कोयले के भंडार को लेकर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 24 सितंबर तक देश के 190 ताप बिजली संयंत्रों में से 80 संयंत्र ऐसे थे, जहां कोयले का भंडार तय जरूरत के 25 फीसदी से भी कम रह गया था। इन संयंत्रों में कुल मिलाकर करीब 2.23 करोड़ टन कोयला उपलब्ध था। हालांकि 26 सितंबर तक बेहद कम भंडार वाले संयंत्रों की संख्या घटकर 77 रह गई, लेकिन इन संयंत्रों में उपलब्ध कोयले की मात्रा भी कम होकर करीब 2.198 करोड़ टन पर आ गई। इससे साफ है कि कम भंडार वाले संयंत्रों की संख्या में मामूली सुधार के बावजूद उपलब्ध स्टॉक में कमी का सिलसिला जारी है। आंकड़ों के मुताबिक 31 अगस्त को इन्हीं संयंत्रों के पास करीब 2.9 करोड़ टन कोयला मौजूद था। इस लिहाज से लगभग एक महीने के भीतर इनके भंडार में करीब 24 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। देश के बिजली संयंत्रों के पास फिलहाल औसतन लगभग सात दिन की जरूरत के बराबर कोयला उपलब्ध बताया जा रहा है। यह मात्रा तय जरूरत का करीब 37 फीसदी है। बिजली की मांग में लगातार उतार-चढ़ाव और ताप बिजली उत्पादन पर निर्भरता के बीच कोयले के स्टॉक में आई यह कमी ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि ताप बिजली देश की कुल बिजली आपूर्ति में बड़ी भूमिका निभाती है।



हालांकि केंद्र सरकार ने मौजूदा स्थिति को कोयले की कमी के रूप में देखने से इनकार किया है। केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सोमवार को कहा कि देश के बिजली संयंत्रों के लिए कोयले की पर्याप्त उपलब्धता है और रेल तथा

मौजूद भंडार तेजी से कम हो सकता है। यही वजह है कि सरकार ने आने वाले महीनों में बिजली उत्पादन को पर्याप्त बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए हैं। बिजली की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने करीब 112 कैप्टिव बिजली संयंत्रों को एक अक्टूबर से 31 दिसंबर तक पूरी क्षमता के साथ संचालित करने का निर्देश दिया है। सरकार ने इसके लिए बिजली अधिनियम की धारा 11 के तहत उपलब्ध आपातकालीन अधिकारों का इस्तेमाल किया है। इस प्रावधान के तहत असाधारण परिस्थितियों में सरकार बिजली कंपनियों और उत्पादन संयंत्रों को अधिक क्षमता से बिजली पैदा करने के निर्देश दे सकता है। इसका उद्देश्य मांग बढ़ने की स्थिति में बिजली की उपलब्धता को बनाए रखना और आपूर्ति व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव को कम करना है। कैप्टिव बिजली संयंत्र मुख्य रूप से औद्योगिक इकाइयों और अन्य बड़े उपभोक्ताओं की अपनी बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इन संयंत्रों की उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल व्यापक बिजली व्यवस्था को सहाय देने में किया जा सकता है। सरकार के ताजा निर्देश को भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत बिजली उत्पादन के उपलब्ध सभी संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल किया जा सके।

कोयले के भंडार में कमी को लेकर सामने आए आंकड़े ऐसे समय में महत्वपूर्ण हैं, जब देश में बिजली की मांग कई कारणों से बढ़ रही है। औद्योगिक गतिविधियों, शहरीकरण, घरेलू खपत और मौसम में बदलाव के कारण बिजली की जरूरत में लगातार परिवर्तन होता रहता है। ताप बिजली संयंत्रों को लगातार चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयले की उपलब्धता जरूरी है। इसलिए खदानों से उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ कोयले को बिजली संयंत्रों तक समय पर पहुंचाना भी महत्वपूर्ण है। देश के बिजली संयंत्रों में कोयले का स्टॉक केवल खदानों में उपलब्ध कुल कोयले से निर्धारित नहीं होता। इसके लिए खदानों से उत्पादन, रेल रैक की उपलब्धता, सड़क परिवहन, संयंत्रों की दैनिक खपत, बिजली की मांग और मौसम जैसी कई परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। मानसून के दौरान खनन और परिवहन प्रभावित होने पर संयंत्रों तक कोयला पहुंचने की गति पर असर पड़ सकता है। यदि उसी अवधि में बिजली की मांग बढ़ जाए तो संयंत्रों के स्टॉक पर दोहरा दबाव पड़ता है। मौजूदा आंकड़ों में भी यही स्थिति दिखाई दे रही है। एक तरफ कम भंडार वाले संयंत्रों की संख्या 80 से घटकर 77 हुई है, वहीं दूसरी तरफ इन संयंत्रों में उपलब्ध कुल कोयला 2.23 करोड़ टन से घटकर 2.198 करोड़ टन रह गया। इसका मतलब है कि केवल संयंत्रों की संख्या देखकर स्थिति का आकलन करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उनके पास उपलब्ध वास्तविक कोयले की मात्रा और प्रतिदिन होने वाली खपत को भी देखना जरूरी है। सरकार का कहना है कि रेल और सड़क मार्ग से कोयले की आपूर्ति लगातार जारी है और किसी अस्थायी व्यवधान को व्यापक कमी नहीं माना जाना चाहिए। वहीं स्टॉक में दर्ज गिरावट यह संकेत देती है कि आने वाले समय में आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा।

गरवी गुजरात हिन्दी

JioTV CHENNAI NO. 2002

Jio FIBER

Jio tv+

Jio Fiber

Daily Hunt

ebaba Tv

Dish Plus

DTH live OTT

Rock TV

Airtel

Amezone Fire

Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही गरवी गुजरात हिंदी चैनल देखिये



अमरेली में शेर की तलाश में बड़ा अभियान, 10 किलोमीटर इलाके में छानबीन; खेतों और झाड़ियों में खोजबीन जारी

अमरेली। गुजरात के अमरेली जिले के राजुला क्षेत्र में वन विभाग के लिए एक शेर को पकड़ना चुनौती बन गया है। नवी बरपटोली गांव के बाहरी इलाके में रेस्क्यू अभियान के दौरान वन विभाग के एक अधिकारी और एक ट्रैकर पर हमला करने के बाद शेर मौके से भाग गया। घटना के बाद वन विभाग ने शेर को सुरक्षित तरीके से पकड़ने के लिए व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया है। करीब 10 किलोमीटर के दायरे में वन विभाग की 11 टीमों रातभर अलग-अलग स्थानों पर शेर की तलाश करती रही। आधुनिक तकनीक, निगरानी उपकरणों और अन्य संसाधनों की मदद से संभावित ठिकानों की जांच की गई, लेकिन अब तक शेर का कोई पुख्ता सुराग नहीं मिल सका है।



पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा त्योहारों के सीजन के दौरान अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से ट्रेन संख्या 09049/09050 दादर-भुसावल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरों को विस्तारित किया गया है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है: ट्रेन संख्या 09049 दादर-भुसावल साप्ताहिक स्पेशल के फेरों को 27 नवम्बर, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी

कोंकण रेलवे द्वारा आयोजित “सृजन के रंग” गोष्ठी में बिखरे कला के विविध हृदयस्पर्शी रंग



मुंबई। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित “सृजन के रंग” कला गोष्ठी में साहित्य और संगीत की विभिन्न विधाओं में बिखरे कलात्मक रंगों ने इसे यादगार बना दिया। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संतोष कुमार झा की अध्यक्षता में बेलापुर स्थित पंचशील विश्राम गृह परिसर में इस कला गोष्ठी का आयोजन 27 सितम्बर, 2026 को किया गया। राजभाषा पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित इस गोष्ठी में मुंबई और नई मुंबई के विभिन्न प्रबुद्ध रचनाकारों ने अपनी प्रतिनिधि काव्य रचनाओं के अलावा लघुकथा एवं संस्मरण तथा लोक



इसके बाद शेतरंजी डीसीएफ, एसीएफ और गिर इस्ट एसीएफ सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। राजुला-जाफराबाद क्षेत्र से वन विभाग की अतिरिक्त टीमों को भी बुलाया गया। इसके बाद शेर की तलाश के लिए व्यापक अभियान शुरू किया गया।

कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के लिए तीन हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के नाम सुझाए, सुनीता अग्रवाल भी शामिल

नई दिल्ली/अहमदाबाद। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए तीन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की। इनमें गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस सुनीता अग्रवाल, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अपरेश कुमार सिंह शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 28 सितंबर 2026 को जारी कॉलेजियम प्रस्ताव में इन नियुक्तियों की सिफारिश दर्ज की गई है।

जस्टिस सुनीता अग्रवाल के नाम की सिफारिश गुजरात हाई कोर्ट के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम है। वह 23 जुलाई 2023 को गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थीं। गुजरात हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार उनका जन्म 30 अप्रैल 1966 को हुआ था और उनकी सेवानिवृत्ति की निर्धारित तारीख 29 अप्रैल 2028 है। वह गुजरात हाई कोर्ट की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश हैं।

जस्टिस सुनीता अग्रवाल का न्यायिक



करियर मुख्य रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ा रहा है। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से वर्ष 1986 में बीएससी की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद अवध विश्वविद्यालय से वर्ष 1990 में कानून की डिग्री हासिल की। 16 दिसंबर 1990 को उन्होंने अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने सिविल, रिट, मूल और वाणिज्यिक मामलों में करीब 21 वर्षों तक वकालत की। इसके बाद 21 नवंबर

अहमदाबाद मंडल द्वारा ‘स्वच्छता ही सेवा 2026’ के अंतर्गत खेल गतिविधियों, स्वच्छता एवं ‘स्वच्छता से समृद्धि’ अभियान का आयोजन

अहमदाबाद: राष्ट्रव्यापी ‘स्वच्छता ही सेवा 2026’ अभियान के अंतर्गत पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन एवं जनभागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत 25 से 26 सितंबर 2026 तक खेल गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता एवं कार्यक्रमों के उपरांत स्वच्छता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया, जबकि 28 एवं 29 सितंबर 2026 को ‘स्वच्छता से समृद्धि’ के अंतर्गत रेलवे स्क्रैप के पुनः उपयोग, प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण तथा अधिकृत रिसाइक्लर्स के साथ प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियाँ आयोजित की गईं। 25 एवं 26 सितंबर 2026 को ‘Sports for Swachhta & Post-Event Cleanliness’ के अंतर्गत रेलवे खेल परिसरों एवं खेल मैदानों में आयोजित खेल गतिविधियों को जीरो-वेस्ट बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। खेल आयोजनों के दौरान उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट को न्यूनतम रखने तथा कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात आयोजन स्थल पर सामूहिक स्वच्छता अभियान चलाकर परिसर



को स्वच्छ बनाए रखने की दिशा में गतिविधियाँ की गईं। इसके माध्यम से खेलों के साथ स्वच्छता एवं पर्यावरणीय जिम्मेदारी को जोड़ते हुए प्रतिभागियों एवं उपस्थित लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। अभियान के अंतर्गत गणेश विसर्जन जैसे

भावनगर मंडल के 05 कर्मचारी डीआरएम संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित, कर्तव्यनिष्ठा एवं त्वरित कार्रवाई से संभावित रेल दुर्घटनाएं टलीं

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में सुरक्षित रेल परिचालन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पांच (05) कर्मचारियों को उनकी असाधारण सतर्कता, कर्तव्यनिष्ठा एवं त्वरित निर्णय क्षमता के लिए वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक श्री सुनिल कुमार गुप्ता की अनुशंसा पर मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा द्वारा डीआरएम संरक्षा पुरस्कार (DRM Safety Award) से सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, भावनगर परा में आयोजित किया गया, जहां सभी सम्मानित कर्मचारियों को प्रशस्ति-पत्र एवं मेडल प्रदान किए गए। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री ऋत्विक शर्मा उपस्थित थे।

सम्मानित कर्मचारियों में श्री अनिल कुमार (उप स्टेशन अधीक्षक-लींबडी), श्री राघु सिंह (कांटेवाला-चुडा), श्री राजेंद्र सिंह राव (कांटेवाला-लींबडी), श्री घनश्याम सी (कांटेवाला-लाटिदंड) एवं श्री जोगिन्दर कुमार (रोटमैन/भूतपूर्व सैनिक-गांधीग्राम) शामिल हैं। इन सभी कर्मचारियों ने दृष्टी के दौरान अपनी सजगता एवं त्वरित कार्रवाई से संभावित रेल दुर्घटनाओं को टालते हुए सुरक्षित रेल संचालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान को रोक़ा गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक ने पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों की सराहना करते हुए उन्हें भावनगर मंडल के सभी रेल कर्मचारियों के लिए प्रेरणास्रोत बताया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की

हमला करने के बाद शेर घटनास्थल से काफी दूर निकल गया हो सकता है। लगातार तलाश के बावजूद यदि उसके पगमाकं या अन्य गतिविधियों के संकेत नहीं मिलते हैं तो आसपास के दूसरे क्षेत्रों में भी उसकी मौजूदगी की जांच करनी पड़ सकती है। इसके लिए वन विभाग की टीमों संभावित मार्गों और शेर के आवागमन वाले क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। हमलावर शेर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने आसपास के इलाकों में कई पिंजरे लगाए हैं। इनमें रिंग केज भी शामिल हैं। इन पिंजरों को ऐसे स्थानों पर लगाया गया है जहां शेर के आने की संभावना मानी जा रही है। इसके साथ ही वनकर्मियों की टीमों अलग-अलग स्थानों पर लगातार निगरानी कर रही है। विभाग का प्रयास है कि शेर को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए बिना

और संवैधानिक मामलों सहित अलग-अलग क्षेत्रों में पीठों की अध्यक्षता की। वह इलाहाबाद हाई कोर्ट की सात न्यायाधीशों वाली उच्च पीठ का भी हिस्सा रही थी, जिसका गठन अधीनस्थ न्यायालयों और उनसे जुड़े बुनियादी ढांचे के मुद्दों पर विचार के लिए किया गया था। जस्टिस अग्रवाल मध्यस्थता के क्षेत्र में भी प्रशिक्षित और प्रमाणित हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न प्रशासनिक समितियों में जिम्मेदारियां निभाईं। अप्रैल 2023 में वरिष्ठतम न्यायाधीश होने के कारण उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। इसके कुछ समय बाद 23 जुलाई 2023 को उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला। गुजरात हाई कोर्ट की मौजूदा न्यायिक संरचना में भी हाल के दिनों में बदलाव हुआ है। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जस्टिस मनाश रंजन पाठक ने 14 सितंबर 2026 को गुजरात हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्यभार, भूमि अधिग्रहण, अंतर-न्यायालय अपील

सुरक्षित तरीके से पकड़कर उपचार और आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके। शेर के बीमार होने की सूचना ने वन विभाग की चिंता और बढ़ा दी है। सामान्य परिस्थितियों में भी किसी शेर की गतिविधियों पर नजर रखना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन बीमारी या कमजोरी की स्थिति में उसके व्यवहार में बदलाव की संभावना को देखते हुए टीमों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ रही है। वन विभाग शेर की गतिविधियों का पता लगाने के साथ-साथ आसपास के ग्रामीणों को भी सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार किसी जंगली जानवर के अचानक मानव संपर्क में आने पर स्थिति तेजी से बदल सकती है। ऐसे में रेस्क्यू अभियान के दौरान प्रशिक्षित टीमों द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों का

सुझाए, सुनीता अग्रवाल भी शामिल

कोर्ट में न्यायाधीश थे। गुजरात हाई कोर्ट की वर्तमान सूची में उनका नाम वरिष्ठ न्यायाधीशों में दर्ज है। जस्टिस सुनीता अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश अभी नियुक्ति की अंतिम प्रक्रिया का एक चरण है। कॉलेजियम की सिफारिश के बाद संबंधित संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई होगी। इसके बाद ही उनकी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति औपचारिक रूप से पूरी होगी। इसी कॉलेजियम प्रस्ताव में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह के नामों की भी सिफारिश की गई है। गुजरात हाई कोर्ट से जुड़े न्यायाधीशों के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की हालिया कड़ी में यह एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। जस्टिस एन.वी. अंजोरिया गुजरात हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहने के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने और बाद में 30 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इसी तरह जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोलो, जो गुजरात हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं और बाद में पटना

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, 29 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ले चुके हैं। अब कॉलेजियम की सिफारिश के बाद गुजरात हाई कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी नजर रहेगी। फिलहाल गुजरात हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जस्टिस सुनीता अग्रवाल ही मुख्य न्यायाधीश के रूप में दर्ज हैं। कॉलेजियम की सिफारिश के बाद उनके सुप्रीम कोर्ट जाने की स्थिति में गुजरात हाई कोर्ट के नेतृत्व को लेकर आगे की संवैधानिक प्रक्रिया मतलबपूर्ण होगी। जस्टिस सुनीता अग्रवाल का नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए सुझाए जाने से न्यायपालिका में उनके लंबे न्यायिक अनुभव और विभिन्न स्तरों पर निभाई गई जिम्मेदारियों को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में जगह मिली है। हालांकि, कॉलेजियम की सिफारिश के बाद नियुक्ति की आगे की प्रक्रिया पूरी होना अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 28 सितंबर का प्रस्ताव इस दिशा में औपचारिक रूप से सामने आया महत्वपूर्ण कदम है।

कोंकण रेलवे द्वारा आयोजित “सृजन के रंग” गोष्ठी में बिखरे कला के विविध हृदयस्पर्शी रंग

कचरे के कम्पोस्टिंग को प्रोत्साहित किया गया। इस पहल का उद्देश्य धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों के बाद उत्पन्न जैविक कचरे का पर्यावरण अनुकूल तरीके से प्रबंधन करना है। 28 एवं 29 सितंबर 2026 को ‘स्वच्छता से समृद्धि’ अभियान के अंतर्गत ‘कबाड़ से जुगाड़/कबाड़ से कला’ की अवधारणा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत रेलवे के अनुपयोगी एवं स्कैप सामग्री, जैसे पुराने सिग्नलिंग उपकरण, कोच के पार्ट्स एवं अन्य धातु स्कैप को रचनात्मक तरीके से उपयोगी वस्तुओं एवं कलाकृतियों में परिवर्तित करने की दिशा में कार्य किया गया। ऐसी उपयोगी वस्तुओं एवं कला स्थापनाओं को रेलवे स्टेशनों, रेलवे कॉलोनियों तथा कार्यशालाओं में प्रदर्शित करने का उद्देश्य अपशिष्ट के पुनः उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा स्वच्छता को रचनात्मकता से जोड़ना है। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक रीसाइक्लिंग पहल के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करने वाले स्टेशनों, जैसे रेलवे स्टेशन एवं कैटीन, को अधिकृत प्लास्टिक रिसाइक्लर्स से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस पहल

के माध्यम से स्टेशन परिसर एवं रेलवे कॉलोनियों से एकत्रित प्लास्टिक कचरे के उचित संग्रहण, पृथक्करण एवं पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत स्टेशनों एवं रेलवे कॉलोनियों से एकत्रित प्लास्टिक कचरे के अधिकृत रिसाइक्लर्स के साथ फॉरवर्ड लिंकेज को मजबूत करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इससे प्लास्टिक अपशिष्ट के वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुकूल निस्तारण को सुनिश्चित करने के साथ-साथ कचरे को संसाधन के रूप में पुनः उपयोग करने की व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। अहमदाबाद मंडल द्वारा ‘स्वच्छता ही सेवा 2026’ के अंतर्गत आयोजित ये गतिविधियाँ स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, अपशिष्ट के पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग एवं जनभागीदारी के संदेशों को प्रभावी रूप से आगे बढ़ा रही हैं। खेल गतिविधियों को जीरो-वेस्ट बनाने से लेकर रेलवे स्क्रैप को रचनात्मक उपयोग में लाने तथा प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण तक, मंडल द्वारा स्वच्छ, हरित एवं टिकाऊ रेलवे परिसर के निर्माण की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

एशियन गेम्स 2026 में गुंजा गुजरात का नाम

उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी के करकमलों से एलावेलिन वलारिवन को 1.33 करोड़ रुपए के खेल प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया

राइफल शूटर एलावेलिन वलारिवन ने शानदार प्रदर्शन से जीते दो सिल्वर मेडल

गांधीनगर । एशियन गेम्स 2026 में राइफल शूटिंग में 2 सिल्वर मेडल प्राप्त करने के लिए गुजरात की प्रतिभाशाली खिलाड़ी एलावेलिन वलारिवन को उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की ऐसी खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें वैश्विक प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक सभी प्रशिक्षण-सुविधाओं के लिए गुजरात सरकार तैयार है। उन्होंने कहा कि जब कोई बेटा या बेटी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करता है, तब उसमें केवल खिलाड़ियों की मेहनत ही नहीं, बल्कि उन्हें संस्कार देकर आगे बढ़ाने



में उनके माता-पिता का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार की डीएलएसएस योजना अंतर्गत संचालित संस्कारधाम परिसर से शिक्षा प्राप्त कर चुकी एलावेलिन वलारिवन ने आज एशियन गेम्स में गुजरात का गौरव बढ़ाया है, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। संस्कारधाम में शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा जब खेल की दुनिया में इस प्रकार इतिहास रचते हैं, तो वे राज्य के अन्य हजारों युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि खेल जगत में

उत्कृष्ट प्रदर्शन बनाए रखने के लिए एलावेलिन वलारिवन को गुजरात सरकार द्वारा शक्तिदूत योजना तथा ऑलंपिक प्रोत्साहन के तहत कुल 1.33 करोड़ रुपए तथा डीएलएसएस योजना एवं सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत 74 लाख रुपए की सहायता दी गई है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा उन्हें कुल 2.41 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया गया है। गुजरात जिनकी कर्मभूमि है; ऐसी शूटर एलावेलिन वलारिवन की उपलब्धियाँ केवल राज्य ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणादायक हैं। अहमदाबाद के



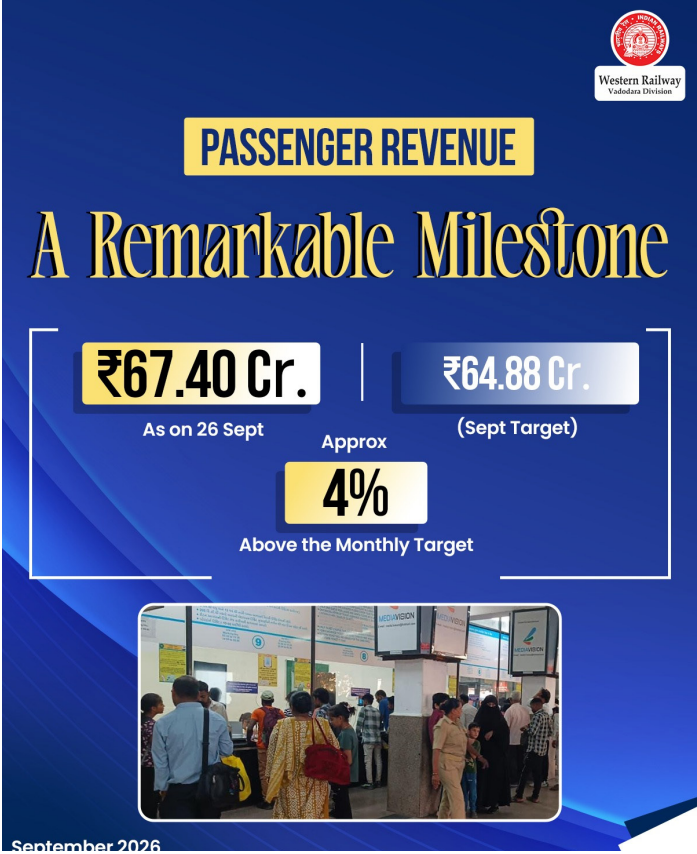
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर से गुजरात सांस्कृतिक वक्तृत्व प्रतियोगिता का शुभारंभ कराया

► **शिक्षा मंत्री तथा राज्य मंत्री की उपस्थिति, विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े**
► **राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग तथा सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन का संयुक्त आयोजन**
► **कक्षा स्तर से लेकर राज्य स्तर तक चार चरणों में विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आयोजित होगी सांस्कृतिक वक्तृत्व प्रतियोगिता, 1100 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे**
► **गुजरात सांस्कृतिक वक्तृत्व प्रतियोगिता केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि युवाओं में संस्कृति के प्रति आदर जगाकर चरित्र निर्माण-राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए एक सक्षम प्लेटफॉर्म है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल**

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात सांस्कृतिक वक्तृत्व प्रतियोगिता-2026 का सोमवार को गांधीनगर से शुभारंभ करते हुए स्पष्ट मत व्यक्त किया कि यह केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि युवाशक्ति में संस्कृति के प्रति आदर जगाकर चरित्र निर्माण तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए एक सक्षम प्लेटफॉर्म है। राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग और सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन के संयुक्त उपक्रम से इस प्रतियोगिता का राज्यव्यापी आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर शिक्षा

वडोदरा मंडल की महत्वपूर्ण उपलब्धि,सितंबर माह के यात्री राजस्व लक्ष्य को समय से पहले 4 प्रतिशत अधिकता के साथ दर्ज किया

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल ने मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के कुशल नेतृत्व में यात्री राजस्व अर्जन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए सितंबर 2026 का निर्धारित मासिक यात्री राजस्व लक्ष्य माह की समाप्ति से 4 दिन पहले ही प्राप्त कर लिया है। मंडल ने 26 सितंबर 2026 तक कुल 67.40 करोड़ का यात्री राजस्व अर्जित किया है, जबकि सितंबर माह के लिए निर्धारित लक्ष्य 64.88 करोड़ था। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री राजेश मथुरिया ने वाणिज्य विभाग की इस उपलब्धि के बारे में बताया कि मंडल ने यात्री राजस्व अर्जन के क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य से 2.52 करोड़ अर्थात 3.88% अधिक राजस्व अर्जित किया है। यह उपलब्धि मंडल द्वारा यात्री सुविधाओं में निरंतर सुधार, प्रभावी टिकट जांच, राजस्व अर्जन के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों तथा रेल यात्रियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में किए जा रहे सतत कार्यों को दर्शाती है। मंडल रेल प्रबंधक श्री श्री राजू भडके कुशल नेतृत्व एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री राजेश मथुरिया के मार्गदर्शन में वडोदरा मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा यात्री सेवाओं को अधिक सुविधाजनक बनाने, टिकट रहित यात्रा पर अंकुश लगाने तथा यात्री राजस्व में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मंडल के



अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समन्वित प्रयासों और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता से यह महत्वपूर्ण उपलब्धि संभव हो सकी है। वडोदरा मंडल यात्रियों को सुरक्षित,

सुगम एवं बेहतर रेल सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ राजस्व अर्जन के निर्धारित लक्ष्यों से आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है।



को उठाया और बताया कि समस्या एक संरचनात्मक खामी है। औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013, नुस्खे वाली दवाओं की कीमतों को सीमित करता है, हालांकि अधिकांश चिकित्सा

उपकरण और उपयोग्य वस्तुएं इस नियंत्रण से बाहर हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी कीमतों और विनियमन से संबंधित जानकारी लगभग पूरी तरह से अनियंत्रित है।

हाल ही में, एक हिंदी समाचार पत्र ने दिल्ली के कई प्रमुख अस्पतालों के मेडिकल स्टोर्स में मिलने वाले उत्पादों की कीमतों की तुलना बाजार की अन्य दुकानों से की

(निडर, निष्पक्ष और तटस्थ छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत गुजरात के 600 कारोबारी संगठनों ने यूपीआई का विरोध जताया है। देश में डिजिटल भुगतान और निवेश को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई के मंचेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। नए नियम 15 अक्टूबर, 2026 से लागू होंगे। इनके तहत 2000 रुपये तक के व्यक्तिगत और व्यापारी भुगतानों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हालाँकि, 2000 रुपये से अधिक के चुनिंदा व्यापारी भुगतानों पर 0.4 प्रतिशत और पूंजी बाजार (म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार आदि) में लेनदेन पर

अनधिकृत रूप से रेलवे परिसर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 147 के तहत 218 मामलों में कार्रवाई की गई। इस प्रकार वर्ष 2026 में अब तक कुल 375 मामलों में रेलवे नियमों के अनुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।

नियमों के पालन के साथ जागरूकता पर भी जोर

भावनगर मंडल RPF द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ रेल कर्मचारियों एवं आमजन को रेलवे सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नियमित रूप से रेलवे परिसर से संभावित अवांछित गतिविधियों की रोकथाम तथा आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। रेलवे कॉलोनियों एवं रेलवे परिसरों के आसपास, स्वच्छ, व्यवस्थित एवं अनुशासित बनाए रखने में रेल कर्मचारियों तथा आमजन की सहभागिता भी महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से RPF द्वारा सुरक्षा संबंधी विषयों पर जागरूकता एवं संवाद को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा

भावनगर मंडल RPF की सतर्कता एवं नियमित निगरानी से भावनगर की रेलवे कॉलोनियों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़, वर्ष 2026 में 375 मामलों में नियमानुसार कार्रवाई

रेलवे परिसरों में सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं अनुशासित वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से भावनगर मंडल के भावनगर टर्मिनस स्थित रेलवे सुरक्षा बल (RPF) पोस्ट द्वारा निरंतर प्रभावी सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। मंडल रेल प्रबंधक, भावनगर, श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन में एवं मंडल सुरक्षा आयुक्त, भावनगर, श्री अजय शर्मा की देखरेख में भावनगर टर्मिनस RPF Post द्वारा भावनगर की मेडिकल कॉलोनी सहित विभिन्न रेलवे कॉलोनियों एवं रेलवे परिसरों में नियमित पैट्रोलिंग, निगरानी एवं जांच की जा रही है।

भावनगर की रेलवे कॉलोनियों में सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए RPF द्वारा रेल कर्मचारियों एवं उनके परिवारों से सुरक्षा संबंधी विषयों पर संवाद किया जा रहा है। साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त निरीक्षण के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है, ताकि रेल कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को सुरक्षित और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

RPF द्वारा रेलवे कॉलोनियों एवं अन्य रेलवे परिसरों में अनधिकृत प्रवेश,



संदिग्ध गतिविधियों, नो-पार्किंग क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग तथा रेलवे नियमों के उल्लंघन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। रेलवे परिसर में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

वर्ष 2026 में 375 मामलों में विधिक कार्रवाई

भावनगर टर्मिनस RPF द्वारा वर्ष 2026 में अब तक कुल 375 मामलों



और संस्कारों का सिंचन करना हमारी जिम्मेदारी है और यह वर्तमान समय की मांग भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनाई गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के फ्रेमवर्क में भी मूल्यनिष्ठ शिक्षा की सिफारिश की गई है। श्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार पाठ्यक्रमों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर बच्चों एवं युवाओं में संस्कृति की जीवंत बनाए रखने तथा युवाधन को व्यसनों से मुक्त रखने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री

द्वारा युवाशक्ति को खेलकूद तथा स्वास्थ्य की ओर मुड़ने और नशामुक्त भारत बनाने के लिए किए गए आह्वान को आत्मसात करते हुए ऐसी वक्तृत्व प्रतियोगिताओं के माध्यम से वैचारिक संस्कृति एवं आत्मविश्वास के सिंचन के लिए प्रेरणा दी।

गुजरात सांस्कृतिक वक्तृत्व प्रतियोगिता क्या है?

इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं में सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों का संवर्धन करने के साथ-साथ व्यक्तृत्व, विचारशक्ति, आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल का विकास करना है।

संगिनी टेक्सटाइल मार्केट की दूसरी मंजिल में लगी भीषण आग, फायरकर्मिं घायल

सूरत। गुजरात के सूरत के सरोली इलाके स्थित संगिनी टेक्सटाइल हब मार्केट में सोमवार शाम अचानक भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। मार्केट की दूसरी मंजिल से अचानक आग की लपटें उठने लगीं और देखते ही देखते घना काला धुआं आसमान में फैल गया। धुएं का गुबार इतनी दूर तक दिखाई दे रहा था कि आसपास के इलाकों में भी लोगों की नजरें घटनास्थल की ओर टिक गईं। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के लिए तत्काल अभियान शुरू किया गया।

बताया गया कि संगिनी टेक्सटाइल मार्केट की दूसरी मंजिल पर सोमवार शाम अचानक आग भड़क उठी। कपड़ा बाजार होने के कारण यहां बड़ी मात्रा में कपड़े और अन्य ज्वलनशील सामग्री मौजूद थी। ऐसे में आग के तेजी से फैलने की आशंका बनी हुई थी। आग की लपटें तेज होने के साथ ही पूरे मार्केट परिसर में हड़कंप मच गया। दुकानदारों और वहां मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग स्तर पर आग बुझाने का काम शुरू किया। आग से निकलने वाला घना काला धुआं आसपास के इलाके में फैल



गया। दूर से ही आसमान में धुएं का बड़ा गुबार दिखाई देने के कारण घटना की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा रहा था। फायरकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर पहले आग को अन्य दुकानों और मार्केट के दूसरे हिस्सों तक फैलने से रोकने की कोशिश की। इसके बाद आग के मुख्य हिस्से पर पानी की बौछार कर उसे नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। कपड़े और अन्य ज्वलनशील सामग्री की वजह से दमकल कर्मियों के सामने चुनौती बढ़ गई थी। आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी घायल हो गया। उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। आग पर काबू पाने की कार्रवाई के दौरान दमकलकर्मिं लगातार जोखिम उठाकर भीतर तक पहुंचने और आग के फैलाव को रोकने

में जुटे रहे। दैर तक फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर सक्रिय रहीं। अधिकारियों की निगरानी में आग के संभावित अन्य हिस्सों की भी जांच की गई, ताकि कहीं अंतर छिपी आग दोबारा न भड़क उठे। फिलहाल संगिनी टेक्सटाइल मार्केट में आग लगने की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। दमकल विभाग और संबंधित अधिकारी आग लगने के कारणों की जांच में जुटे हैं। शॉर्ट सर्किट, विद्युत वायरिंग में खराबी या किसी अन्य कारण की संभावना को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। आग से कितना आर्थिक नुकसान हुआ है, इसका आकलन भी आग पूरी तरह बुझने और प्रभावित दुकानों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद किया जाएगा। सूरत देश के प्रमुख कपड़ा कारोबार केंद्रों में शामिल है और शहर के कई

यूपीआई पर एमडीआर शुल्क का विरोध: गुजरात के 600 कारोबारी संगठनों ने गांधी जयंती पर ‘यूपीआई का उपयोग नहीं’ करने और केवल नकद लेनदेन करने की घोषणा की



0.02 प्रतिशत का एमडीआर निर्धारित किया गया है। , जिसका कारोबारी संगठनों ने विरोध किया है। अहमदाबाद समेत राज्य के सभी व्यापारी सरकार के एमडीआर शुल्क से छूट की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। राज्य

बैंकिंग सेवाओं पर मंडरा हा संकट टला, आईबीए से बातचीत के बाद यूएफबीयू ने स्थगित किया तीन दिवसीय आंदोलन

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रस्तावित तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल टलने से सोमवार को देशभर में बैंक शाखाएं सामान्य रूप से खुलीं और बैंकिंग सेवाएं सुचारु रूप से संचालित हुईं। इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) और बैंक यूनियनों के बीच रविवार देर रात हुई बातचीत के बाद यूनियनों ने हड़ताल स्थगित करने का फैसला किया। इससे उन लाखों ग्राहकों को राहत मिली, जिन्हें हड़ताल की स्थिति में नकद निकारी, जमा, चेक से जुड़े काम और अन्य बैंकिंग सेवाओं में परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने सोमवार से तीन दिनों तक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। यह हड़ताल बैंकों की छमाही क्लोजिंग के महत्वपूर्ण समय के दौरान प्रस्तावित थी। ऐसे समय में बैंकों में वित्तीय वर्ष की निर्धारित प्रक्रियाओं और खातों से जुड़े कार्यों का दबाव रहता है। हड़ताल के कारण बैंक शाखाओं के कामकाज में साथ-साथ ग्राहकों और व्यापारिक गतिविधियों पर भी असर पड़ने की आशंका जलाई जा रही थी। हालांकि, आईबीए के साथ हुई बातचीत के बाद आंदोलन को

भारत मिशन, विकसित भारत@2047 : आत्मनिर्भर भारत, संस्कृति और संस्कार : राष्ट्र के अस्तित्व का आधार, कड़वे फल हैं क्रोध के, भारतीय नागरिक के रूप में कर्तव्य : संविधान के अनुच्छेद 51(क) को शामिल किया गया है।

यह जीएसबीएस-2026 केवल वक्तृत्व प्रतियोगिता नहीं, बल्कि युवाशक्ति में संस्कार, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण की भावना का संवर्धन करने वाला व्यापक अभियान है। शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा ने इस अवसर पर प्रतियोगियों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत बनाने का दायित्व युवाशक्ति के कंधों पर है। इस वक्तृत्व प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं में अपने विचारों की अभिव्यक्ति के साथ आत्मविश्वास का भी सिंचन होगा, जो सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरक शक्ति बनेगा।

शिक्षा मंत्री ने एनईपी में भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ने के लिए मातृभाषा शिक्षा की हिमायत के संदर्भ में कहा कि मातृभाषा के माध्यम से ही विद्यार्थी मातृभूमि की जड़ों से जुड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि मातृभूमि के साथ ऐसा तादात्म्य एवं जुड़ाव ही विचारों की व्यापकता से प्रधानमंत्री द्वारा दी गई वसुधैव कुटुम्बकम् की अवधारणा को साकार करता है। शिक्षा राज्य मंत्री श्री त्रिकमभाई छंगा

ने स्वागत संबोधन के माध्यम से सभी का स्वागत किया। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य के युवाओं में संस्कार सिंचन का महाकुंभ यह प्रतियोगिता बनेगी।

सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन के संस्थापक एवं भारत सरकार के पूर्व आरटीआई आयुक्त श्री उदय माहुरकर ने आज के आधुनिक तथा पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण के दौर में युवा पीढ़ी में सांस्कृतिक मूल्यों को पुनः जागृत करने के इस अभियान को राष्ट्र निर्माण का विराट कार्य बताया। उन्होंने जोड़ा कि विशेष रूप से मोबाइल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्याप्त विकृति के समक्ष युवाओं को संस्कृति एवं चरित्र निर्माण की ओर मोड़ने के लिए ऐसे आयोजनों को सेव कल्चर सेव इंडिया फाउंडेशन अधिक व्यापक स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस प्रतियोगिता की सफलता के लिए युवा जैनाचार्य महर्षि विजयजी महाराज, पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामीजी, पूज्य श्री रमेशभाई ओझा के शुभकामना संदेश भी प्राप्त हुए।

इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मुकेश कुमार, उच्च शिक्षा आयुक्त श्री दिलीप राणा, केसीजी वसुधैव कुटुम्बकम् की अवधारणा को साकार करता है। शिक्षा राज्य मंत्री श्री त्रिकमभाई छंगा

आपातकालीन निकास और बिजली की वायरिंग की नियमित जांच जरूरी है। साथ ही दुकानदारों और कर्मचारियों को आग लगने की स्थिति में तत्काल उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी होना भी महत्वपूर्ण है।

इससे पहले सूरत के कामरेज इलाके में मानसरोवर रिजिडेंसी के एक फ्लैट में LPG गैस के रिसाव के बाद आग लगने की घटना सामने आई थी। आग तेजी से फैलने के कारण घर में रखा सामान जलकर राख हो गया था। हादसे में एक बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गए थे। घटना की सूचना मिलने के बाद कामरेज फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कामरेज की घटना में भी LPG गैस का रिसाव किस वजह से हुआ और आग किस परिस्थिति में भड़की, इसकी जांच की जा रही है। लगातार सामने आ रही आग की घटनाओं ने घरों से लेकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और बड़े बाजारों तक अग्नि सुरक्षा के इंतजामों की नियमित जांच की जरूरत को रेखांकित किया है। संगिनी टेक्सटाइल मार्केट की घटना में भी जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारण और नुकसान की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।

कोड मशीनों और बोर्डों को काले कपड़े से ढक देगे और केवल नकद भुगतान पर ही लेन-देन करेंगे। इसके अलावा, यह आशंका भी है कि इस विरोध प्रदर्शन के दिन लगभग 50 करोड़ रुपये के लेन-देन सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। सरकार यूपीआई पर शुल्क लगाकर पैसा वसूलना चाहती है। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। छोटे व्यापारी जिन्होंने यूपीआई को अपनाया है और वर्षों से इसका उपयोग कर रहे हैं, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप पैसा वसूलना चाहते हैं, तो आप बैंकिंग प्रणाली में कोई भी छोटाय वादा प्रवाधान लगाकर इसे वसूल सकते हैं।

के लगभग 600 व्यापारी संघ इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। आंदोलनवाद् यूनियन, मोबाइल यूनियन, इलेक्ट्रॉनिक्स यूनियन, कपड़ा बाजार और आभूषण बाजार के व्यापारी यूपीआई लेनदेन स्वीकार नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, गांधी जयंती के दिन सभी व्यापारी अपनी क्यूआर



फिलहाल टाल दिया गया। सूत्रों के अनुसार रविवार देर रात आईबीए और यूएफबीयू के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में बैंक यूनियनों की विभिन्न मांगों पर चर्चा हुई। बातचीत के दौरान यूनियनों को उनकी प्रमुख मांगों पर आगे विचार और समाधान की दिशा में कदम उठाने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद यूएफबीयू ने प्रस्तावित हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया। हड़ताल टलने के साथ ही सोमवार को बैंक शाखाओं के नियमित रूप से खुलने और सामान्य कामकाज जारी रखने का रास्ता साफ हो गया। बैंक यूनियनों का प्रमुख मांगों में सप्ताह में पांच दिन काम करने की व्यवस्था लागू करना शामिल है। यूनियनों का लंबे समय से कहना रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र में कामकाज के दिनों को लेकर नई व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। इसी मांग को लेकर यूनियनों की ओर से आंदोलन का कार्यक्रम घोषित किया गया था। प्रस्तावित हड़ताल के दौरान बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना थी, लेकिन बातचीत के बाद फिलहाल टकराव की स्थिति टल गई है। यूएफबीयू के अनुसार, बाकी शनिवारों को अवकाश घोषित करने के मुद्दे पर आगे विचार के लिए आईबीए और यूएफबीयू

की एक उच्चस्तरीय समिति तत्काल गठित की जाएगी। यह समिति इस मुद्दे से जुड़े विभिन्न विकल्पों पर विचार करेगी और संबंधित पक्षों के साथ चर्चा के बाद ऐसा समाधान तलाशने का प्रयास करेगी, जो बैंक कर्मचारियों के साथ-साथ ग्राहकों और अन्य हितधारकों के लिए भी स्वीकार्य हो। बैंक यूनियनों के इस फैसले के बाद सोमवार को देशभर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सामान्य रूप से खुले। शाखाओं में ग्राहकों को नियमित सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। हड़ताल स्थगित होने से बैंकिंग व्यवस्था में संभावित व्यवधान भी फिलहाल टल गया। विशेष रूप से छमाही क्लोजिंग के समय बैंक बंद रहने से होने वाली अतिरिक्त परेशानी की आशंका भी समाप्त हो गई। बैंकिंग सेवाओं का निष्पाद संचालन आम ग्राहकों के साथ-साथ व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। बैंक शाखाओं के माध्यम से योजना बड़ी संख्या में नकद लेनदेन, चेक संबंधी काम, खातों से जुड़े कार्य और अन्य सेवाएं संचालित होती हैं। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जारी रहने के बावजूद कई ग्राहक अभी भी शाखाओं में जाकर विभिन्न बैंकिंग कार्य पूरा करते हैं।